Total Pages : 20

Not to be filled by the Candidate

(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहिचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओ के नाम अथवा कोई भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखे कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी को अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक नहीं लिखने चाहिये। किसी भी परिस्थिति में पुरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. प्रश्न द्वारा अपेक्षित भाषा, अंग्रेजी या हिन्दी में ही उत्तर दीजिये।
8. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र अभिजागर से कह कर उसे बदलवा लें या अभिजागर के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
9. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

SI

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll Number, Name, Address, Mobile Number/ Telephone Number, Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book Shall be provided in any case.
7. Attempt answer only in the language, English or Hindi, as required by the question.
8. In case the Question paper – cum Answer booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
9. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

Attempt all 05 Questions. Question No. 1, 3 and 5 carry 10 marks each. Question No. 2 carries 5 marks. Question No. 4 carries 15 marks.

समस्त 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1, 3 एवम् 5 प्रत्येक के 10 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 2 के 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 4 के 15 अंक निर्धारित है।

Question No.1: **(10 Marks)**

Translate the following passage in Hindi.

नीचे दिये गये लेखांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिये।

"Law is the frame of civilisation. That the Rule of Law should prevail everywhere is now axiomatic. In our country, which has different faiths and diverse social systems, Law has given us a new approach to the changing ways of life. Law has become a rational system in a society still wedded to archaic or conservative ideas, changeable to meet the changing needs, particularly in economic and social matters. For more than a century law has proved that it can be strong engine for bringing about changes, even of a far-reach character. One of the noblest provisions in our Constitution is the one for the abolition of untouchability, included as one of the Fundamental Rights in the Constitution.

Our legal system, therefore, in a sense is a composite one. We have codified our statutory laws, largely derived in their juristic conception from the West, and adopted them to meet our changing needs. The other is the Personal Law, represented through religion, custom, usage and local tradition. On the High Court will fall a very great responsibility to apply both the statutory and customary laws. The range of the former will naturally be widened on account of the important constitutional changes, which have taken place in Rajasthan. The application of both these will inevitably require knowledge understanding and a sympathy with the type of society which has existed for centuries in Rajasthan and which has not been modified to the same extent as in other parts of India.

The broadening of the basis of freedom and the rapid democratisation of the administration place another heavy responsibility on our High Court. The rights guaranteed to the citizen by the State can only be upheld by the Judges of the land. The only bullwork against unconstitutional or arbitrary encroachment of the citizen's liberty in the Judiciary. The new Constitution confers on the citizens, throughout India certain fundamental rights. The custodians and guarantors of those rights will be our judges. This is a new responsibility as well as a great privilege being conferred on our Judiciary. The enhancement of the prestige of the Judiciary in the eyes of the people will depend largely on the manner in which the responsibility is discharged to the satisfaction, and in the interests of the citizens of the country."

Question No.2: **(05 Marks)**

Translate the following passage in Hindi.

नीचे दिये गये लेखांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिये।

"Whilst High Court of Madhya Pradesh (Mr Justice Sheth), set aside the reasoning of the District Judge who had relied on the doctrine of inherent powers, it held that the Court was not powerless because of want of a statutory provision to award interim damages in a suit for tort. The Judge traced this power not to the inherent powers of the court but to the common law, and he rationalised and upheld the ultimate order of the District Judge whilst disagreeing with his reasoning. He said that the law of tort was and is part of the common law of India adopted and adapted from the common law of England.

The judgment of Justice Sheth constitutes the only precedent in India for grant of interim relief in a suit for damages for tort. It also underscores the need for judges to avoid literal and parochial approaches to interpret the law, when justice would be better served by bringing to bear larger humane sensitivities to their tasks. As the American philosopher Martha C. Nussbaum has said: 'Judges must educate not only their technical capacities but also their capacity for humanity'."

Question No.3: **(10 Marks)**

Translate the following passage in English.

नीचे दिये गये लेखांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिये।

"भारत ने जगत्–गुरू होने का एक भ्रम पाल रखा है। इससे जितनी जल्दी नजात मिले, उतना अच्छा। भारत ने यदि मानव सभ्यता को कुछ दिया है, तो उसने बहुत कुछ लिया भी है। इस आदान–प्रदान के बिना हमारा सामाजिक–सांस्कृतिक विकास अवरूद्ध हो जाता।

हमारा दूसरा जातीय भ्रम है हमारी समाज–व्यवस्था के आदर्श होने का। यदि हमारी व्यवस्था आदर्श और स्वयंपूर्ण थी तो वह समय–समय पर उठने वाली गंभीर समस्याओं का हल क्यों नहीं खोज सकी? विसंगतियों के कारण हमारी दुर्दशा क्यों हुई?

निःसंदेह हमारे पास उच्च आदर्शों और लक्ष्यों का अनमोल खजाना है, पर इनके संदर्भ में ही हम तीसरा भ्रम पाल रहे है। हमारे ऊँचे आदर्श हमारी जिंदगी में रसे–बसे नहीं हैं, हमारी कथनी

और करनी में भारी अन्तर है। क्या हम हृदय पर हाथ रख पूरी सच्चाई से यह कह सकते हैं कि हमारा आचार–विचार सत्य पर आधारित है? अहिंसा के देश में हिंसा का ज्वालामुखी क्यों फूट रहा है? अपरिग्रह की दुहाई देने वाले समाज में उपभोक्ता संस्कृति क्यों पनप रही है?

इक्कीसवीं सदी में प्रवेश की चर्चा चौथे भ्रम का जन्म दे रही है। हमारा ध्यान उच्च विज्ञान और तकनीकी पर केंद्रित है, हम उनके सांस्कृतिक पक्ष पर बहुत कम विचार कर रहे हैं। मानवीय मूल्यों और मानसिकता पर उनका क्या प्रभाव होगा? क्या यांत्रिकता और अमानवीकरण ही हमारे भविष्य है?

सच्ची भारतीयता की तलाश का आग्रह है कि हम जगत्गुरू होने का दंभ छोड़कर यथार्थ की भूमि पर उतरें और अपनी समसामयिक दशा पर विचार करें। पुनर्गठन के लिए हमारे समाज को नये लक्ष्य और साधन चाहिए। भारतीय परंपराओं के अक्षय स्त्रोत से हमें भारतीयता के नये प्रतीक और मूल्य चुनना है। ये तत्व ऐसे हों जिनके द्वारा हम आज और आने वाले कल की चुनौतियों का सामना कर सकें।"

Question No.4: **(15 Marks)**

Write the precis of the following passage in Hindi.

नीचे दिये गये लेखांश का हिन्दी में सार लिखिये।

"इस भोगवादी औपचारिक शिक्षा के कारण मनुष्य जितना जोर अपने अधिकारों पर दे रहा है उतना अपने कर्त्तव्यों पर नहीं दे रहा है।मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि अधिकारों का भोग कर्त्तव्यों के पालन का ही फल हो सकता है और यदि हम अपना अपना कर्त्तव्य पूरा करें तो हमें अधिकार भी प्राप्त होंगे। अधिकार तथा कर्त्तव्य के बीच संबंध की जो अटूटता है उसे मनुष्य भूलाता जा रहा है और अधिकार प्राप्ति के लिए (बल्कि कहना चाहिए कि शेष समाज की तुलना में अतिविशिष्ट अधिकार प्राप्ति के लिए) आज का मनुष्य निकृष्ट से निकृष्ट साधन अपनाने को तैयार है। जब भोग की साधन सामग्री कम है और उसके विशिष्ट दावेदारों (अर्थात शिक्षित लोगों) की तादाद दिन दूनी रात चौगुनी बंढ़ती जा रही है तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि मनुष्य समाज की संपदा में से प्रथम तो अधिक से अधिक लूटने का प्रयत्न करेगा और इस प्रकार जो भी लूट हाथ लगेगी उसे एकांत में सुरक्षित करके अकेले में भोगेगा क्योंकि यदि एकान्त तथा अकेलेपन का सहारा नहीं लिया जाय तो भोग संपदा को बांटना होगा। इस प्रकार भारत में एक तरफ घोर दरिद्रता है और दूसरी तरफ काल्पनातीत वैभव एवं ऐश है। आज, भारत का मनुष्य अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने भाई से बंट रहा है, कट रहा है क्योंकि मिलकर रहने से बांटकर खाना होता है जिस-का संस्कार हमारी औपचारिक शिक्षा देती ही नहीं है। इस प्रकार हमारी शिक्षा हमारे राष्ट्र का असंयोजन अर्थात् बिखराव करती जा रही है। किसी भी बस्ती में यद्यपि मनुष्यों की अपार भीड़ तो मौजूद है, पर मनुष्यों के बीच कोई भी रागात्मक संबंध नहीं है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा निर्मोही बर्ताव करता है मानो एक की पीड़ा दूसरे के हृदय को स्पर्श ही नहीं करती ।

हम लोग जिस रीति से टिकिट की खिड़की पर, अथवा रेल के डिब्बों या बस में चढ़ते समय बर्ताव करते है, जिस प्रकार स्कूलों में या नौकरियों में भरती होने के लिए गलाकट प्रतिस्पर्धा एवं भ्रष्टाचार चलता है, उससे सिद्व होता है कि परिस्थिति कितनी भयावह, निराशाजनक तथा असाध्य सी हो चली है आज जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है तो वह एक मित्र या साथी को पाने की भावना से आश्वस्त नही होता बल्कि एक प्रतिस्पर्धा से मुठभेड़ हो जाने के भय से चिंतित हो जाता है। आज हर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को या तो अपने शिकार या शिकारी के रूप में देखता है। आज प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से निरन्तर सतर्क तथा सावधान रहनाहोता है। सारी परिस्थिति अत्यंत भयानक तथा खतरनाक है। जैसे–जैसे मनुष्य अपने पृथक एवं संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति की सीमा में अपने आपको बंद करता जा रहा है, वैसे–वैसे उत्पादन घट रहा है और असुरक्षा बढ़ रही है और जैसे–जैसे उत्पादन घटता है तथा असुरक्षा बढ़ती है वैसे–वैसे मनुष्य और ज्यादा पृथक्तावादी, संकीर्ण मनोवृत्ति वाला तथा असहयोगी बनता जा रहा है। तो इस दुश्चक्र का कोई अंत नहीं दिखता और यह आज की शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।"

Question No.5: **(10 Marks)**

Write the precis of the following passage in English.

नीचे दिये गये लेखांश का अंग्रेजी में सार लिखिये।

"What emerges is that in a limited government under a written constitution all organs of the State are creatures of the Constitution and have to act and function under the Constitution and in consonance therewith. What is, therefore, supreme is the Constitution and what obtains is constitutional supremacy, the judiciary having the last word in the interpretation of the Constitution. Judicial supremacy is really a euphemism for constitutional supremacy or the supremacy of the Constitution with the judiciary – constituted as its monitor, defender and protector. And what is the sanction to keep the judiciary also within the bounds of its powers? It is, in a large measure, the judges' own sense of self-restraint.

There is no assurance that judges will interpret the mores of their day more wisely and truly than other men. But the power must be lodged somewhere; it has been lodged in the judges and if they have to fulfill their function as judges, it could hardly be lodged elsewhere. As Lord Denning said, "someone has to be trusted, let it be the judges".

As Frankfurter J observed, "Our system is built on the faith that men set apart for this special function, freed from the influences of immediacy and from the deflections of worldly ambition will be able to take a view of the longer range than the period of responsibility entrusted to the legislatures." And as learned Hand J said, pointing to the shelves of his law library, "To whom am i responsible? To those books about us. That's to whom I am responsible."

The reality is that the Constitution contains a melange of powers. No single institution is even remotely supreme. It is as it should be and will probably always be so. Some struggle and tension do occasionally arise. Reciprocal influence is a continuing process.

In the field of constitutional law the delicate balance between the various institutions whose sound and lasting quality Dicey in The Law of the Constitution likened to the work of bees when constructing a honeycomb is maintained to a large degree by the mutual respect which each institution has for the other. In British Railways Board v. Pickin, Lord Reid observed that for a century or more both Parliament and the courts have been careful to act so as not to cause conflict between them. This is as much a prescription for the future as it was for the past.

This is the profound truth and is equally relevant in India too!"